अन्त तक राज्य सरकार 800 एकड़ भूमि पर 304 परिवारों के पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण करने की आशा है। 1966-67 में, 955 परिवारों को 6,633 एकड़ कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया गया ।

जहां तक पंचायतों की भूमि का सम्बन्ध है, भूमि प्रबन्ध समिति को उस समय तक भूमि किसी को देने से रोक दिया गया है, जब तक कि कानून में संशोधन नहीं कर दिया जाता जिसके द्वारा तहसीलदार भूमि प्रबन्ध समितियों के प्रस्ताव का भूमिहीन हरिजनों और सेवा निवृत्त सैनिकों को भूमि के आवंटन में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर पूर्व निरीक्षण करने का अधिकारी होगा । इस संशोधन के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक विधेयक तैयार है ।

ASSISTANCE TO CONSUMER COOPERATIVES FOR MANUFACTURE OF BREAD

4613. SHRI JAGESHWAR YADAV: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give financial assistance to the Consumer Cooperative Stores to enable them to set up small plants for the manufacture of bread;

(b) if so, the quantum of assistance proposed to be given; and

(c) the number of plants to be set up under the Consumer Cooperative Stores?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) Yes, Sir. However, the Central Government does not provide financial assistance directly to consumer cooperatives. Assistance is provided to the State Government who actually finance the consumer cooperative stores.

(b) The pattern of assistance under the scheme is as follows:—

(i) Loan to the State Governments for providing assistance to a consumer cooperative towards block capital expenditure of an approved bakery unit up to 100% where such expenditure does not exceed Rs. 1 lakh and up to 40% where it exceeds Rs. 1 lakh.

(ii) Grant to the State Governments for providing managerial subsidy to a consumer cooperative for a bakery unit up to 100% of the approved expenditure during the first year, 66⅔% during the second year and 33⅓% during the third year.

(c) No fixed number of bakery plants has been envisaged. It will depend upon response from consumer cooperatives. So far assistance has been sanctioned for 3 units.

बिहार में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में डाकघर

4614. श्री क० मि० मधुकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में डाकघर नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में डाकघर खोले जा चुके हैं तथा कितने क्षेत्रों में अभी तक कोई डाकघर नहीं है; और

(ग) दो हजार की जनसंख्या के लिये एक डाकघर खोलने के अपने लक्ष्य को सरकार का विचार कब तक पूरा करने का है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे ग्राम पंचायतों वाले गांव—

(i) जिन में डाकघर हैं—4,427

(ii) जिन में डाकघर नहीं हैं—4,466।